सहकारिता क्षेत्र में भ्रष्टाचार

786. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारिता क्षेत्र में विद्यमान भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार देशव्यापी सर्वेक्षण कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(ग) क्या कभी पहले ऐसी जांच कराई गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). सहकारिता राज्य विषय होने के कारण राज्यों में सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण और उन्हें मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर सहकारी समितियों के कार्यसंचालन में ईमानदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये हैं । इनमें यह सुनिश्चित करना शामिल है :—लेखाओं को उचित रूप से रखना, समय से लेखा-परीक्षा करना, बड़े पैमाने पर सहकारी संस्थाओं में समवर्ती लेखा-परीक्षा आरम्भ करना, और लेखा-परीक्षा में पाई गई कमियों को सुधारने के लिए कारगर अनुवर्ती कार्यवाई करना । इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में राज्य सहकारी कानूनों में यह व्यवस्था करने के लिए भी सुझाव दिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आदि जैसे मुख्य पद कितने कार्यकालों तथा कितनी संस्थाओं में ग्रहण किये जा सकते हैं । सूचित की गई अनियमितताओं के विशिष्ट मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकारें आवश्यक जांच करती हैं और सुधार करने के लिए कदम उठाती हैं ।

Irregularities in Marine Products Export Development Authority

787. SHRI R. K. AMIN: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether a special Audit was necessitated to find out the irregularities in the Marine Products Export Development Authority; and

(b) if so, the findings thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) After the present Chairman, Marine Products Export Development Authority took over, some aspects of expenditure were got checked by a Cost Accountant in February 1977. A regular internal audit of Marine Products Export Development Authority accounts was also undertaken in May, 1977 by the Internal Audit Wing of the Ministry of Commerce.

(b) The report of the Internal Audit Party has just been received and is being examined. The Government has not received the report of the Cost Accountant.

Compensation for Properties left in Former East Pakistan and West Pakistan

788. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) latest figures separately about the applications received by Government regarding compensation for "properties" left in West Pakistan and former East Pakistan by displaced persons declared as "enemy properties":